भारत बनाएगा कपास में नई पहचान

सफेद सोना' से मजबूत होगी कृषि और वस्त्र अर्थव्यवस्था, गुणवत्ता, तकनीक और ब्रांडिंग पर सरकार का फोकस

नई दिल्ली, 20 जुलाई भारत अब कपास यानी 'सफेद सोना' के क्षेत्र में अपनी वैश्विक पकड़ और मजबूत करने की तैयारी में है. कृषि और वस्त्र उद्योग की रीढ़ मानी जाने वाली कपास फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने वर्ष 2031 तक 498 लाख गांठ उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है.

इसके लिए कपास उत्पादकता मिशन शुरू किया गया है, जिसमें आधुनिक तकनीक, जलवायु अनुकूल खेती और उच्च गुणवत्ता वाले रेशे वाली किस्मों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां कपास की चारों प्रमुख प्रजातियों की खेती की जाती है. क्षेत्रफल के लिहाज से भारत दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है. अब सरकार का लक्ष्य सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि भारतीय कपास की गुणवत्ता, उत्पादकता और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान को मजबूत करना है. वर्ष 2025-26 के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, देश में कपास उत्पादन 290.91 लाख गांठ रहा है, जबकि घरेलू खपत 328 लाख गांठ तक पहुंच गई. कपास व्यापार में एक गांठ को मानक इकाई माना जाता है, जिसका वजन 170 किलोग्राम होता है. वैश्विक रेशा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी करीब 19 से 23 प्रतिशत तक है. यह फसल देश के करीब 60 लाख किसानों की आय का प्रमुख स्रोत है.

> कपास किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गई है. वर्ष 2026-27 सीजन के लिए मध्यम रेशे वाली कपास का एमएसपी 8,267 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे रेशे वाली कपास का एमएसपी 8,667 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. भारतीय कपास की पहचान को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए 'कस्तूरी कॉटन भारत' ब्रांडिंग कार्यक्रम भी शुरू किया गया है. इसमें ट्रेसबिलिटी, ब्लॉकचेन और क्यूआर कोड आधारित प्रमाणन व्यवस्था लागू की जा रही है.

अल्ट्राटेक को 2,604 करोड़ रुपये का मुनाफा

मुंबई, 20 जुलाई आदित्य बिरला समूह की निर्माण सामग्री बनाने वाली कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में समेकित आधार पर 2,604 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ जो सालाना आधार पर 17.24 प्रतिशत अधिक है.

कंपनी ने सोमवार को वित्तीय परिणामों की घोषणा की. उसने बताया कि तिमाही के दौरान उसकी शुद्ध बिक्री 24,465 करोड़ रुपये रही. यह पिछले वित्त वर्ष की शुद्ध बिक्री से 16.28 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है. तिमाही में घरेलू बिक्री 3.92 करोड़ टन रही जो सालाना आधार पर 13.1 प्रतिशत अधिक है. कंपनी का परिचालन लाभ भी 12.09 फीसदी की वृद्धि के साथ 5,146 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. प्रति टन परिचालन लाभ 1,214 रुपये से बढ़कर 1,198 करोड़ टन हो गया.

ब्रिक्स बैठक में डिजिटल न्याय व्यवस्था पर मंथन

डिजिटल तकनीक से न्याय प्रक्रिया को तेज बनाने पर जोर

साइबर अपराध और सीमा पार अपराधों से निपटने की बनेगी रणनीति

नई दिल्ली, 20 जुलाई भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग द्वारा ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की आठवीं बैठक का आयोजन 20 और 21 जुलाई को किया जा रहा है. वर्चुअल माध्यम से होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता भारत के महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी करेंगे.

इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के अभियोजन प्रमुख आपराधिक न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने, डिजिटल तकनीक के उपयोग और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे.बैठक का मुख्य विषय 'अभियोजन के दृष्टिकोण से आपराधिक न्याय प्रक्रिया में अनुभवों और बेहतर कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान' रखा गया है.

> बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ताआधारित न्याय व्यवस्था, आपराधिक मामलों के डिजिटलीकरण, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के प्रबंधन और मामलों के जल्द निपटारे पर विशेष चर्चा होगी. इसका उद्देश्य तकनीक के माध्यम से न्याय प्रक्रिया को सरल, तेज अधिक भरोसेमंद बनाना है.सदस्य देश पीड़ित-केंद्रित न्याय व्यवस्था को मजबूत करने, अभियोजन सेवाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने और जनता का न्याय प्रणाली पर विश्वास कायम रखने के उपायों पर भी विचार करेंगे. इसके अलावा साइबर अपराध, सीमा पार वित्तीय अपराध और पर्यावरण से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा.

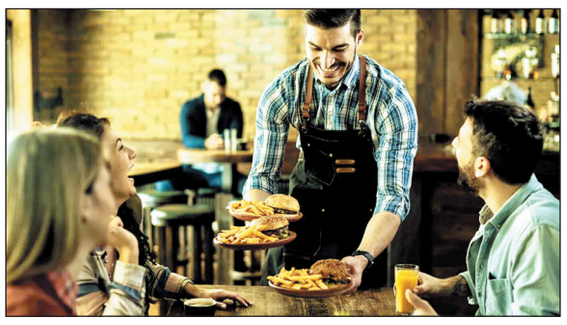

रेस्टोरेंट बिल में जबरन सर्विस चार्ज वसूला तो होगी कार्रवाई

ग्राहक मना कर सकता है अतिरिक्त शुल्क देने से

शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर करें संपर्क

नई दिल्ली, 20 जुलाई होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद अगर आपके बिल में बिना बताए सर्विस चार्ज जोड़ दिया जाता है, तो अब आपको इसे चुपचाप भरने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट ग्राहक की सहमति के बिना बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता.

यह शुल्क पूरी तरह से स्वैच्छिक है और ग्राहक अपनी इच्छा के अनुसार ही इसका भुगतान कर सकता है. जबरन सर्विस चार्ज वसूलना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा.केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है. प्राधिकरण के अनुसार, कई होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों को जानकारी दिए बिना बिल में अतिरिक्त शुल्क जोड़ देते हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता है.

ऐसे मामलों में ग्राहक शिकायत दर्ज कराकर अपनी राशि वापस मांग सकते हैं.वीकेंड या खास मौकों पर परिवार और दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने का चलन बढ़ गया है. ऐसे में कई बार ग्राहक बिल की कुल राशि पर ध्यान नहीं देते और उसमें जुड़े अतिरिक्त चार्ज का भुगतान कर देते हैं. लेकिन नियमों के अनुसार, सर्विस चार्ज कोई अनिवार्य शुल्क नहीं है.

> अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट के बिल में बिना अनुमति सर्विस चार्ज जोड़ा जाता है, तो ग्राहक पहले वहां के प्रबंधन से इसे हटाने के लिए कह सकता है. समाधान नहीं मिलने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. उपभोक्ता बिल की कॉपी, भुगतान रसीद और अन्य जरूरी जानकारी के साथ शिकायत कर सकते हैं. सरकार का उद्देश्य है कि ग्राहकों को पारदर्शी बिल मिले और उनसे किसी भी तरह का अनिवार्य अतिरिक्त शुल्क न वसूला जाए.

कोल इंडिया के लिए सौर परियोजना शुरू

नई दिल्ली, 20 जुलाई केपीआई ग्रीन एनर्जी ने गुजरात में कोल इंडिया के लिए 200 मेगावाट / 269 मेगावाट (डीसी) सौर ऊर्जा क्षमता परियोजना का निर्माण कर उसे सफलतापूर्वक चालू कर दिया है.

कंपनी की ओर से सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि खावड़ा में गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लि सोलर पार्क में स्थापित यह परियोजना 300 मेगावाट (एसी) / 405 मेगावाट (डीसी) के ग्रिड से जुड़ी, सौर बिजली परियोजना है कि जिसमें फोटोवोल्टिक (पीवी) पाल जमीन के ऊपर बिछाए गये हैं. परियोजना का हिस्सा है, जिसे केपीआई ग्रीन एनर्जी ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन) आधार पर विकसित कर रही है. इस परियोजना को गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (गेडा) द्वारा प्रमाणित किया गया है.केपीआई ग्रीन एनर्जी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक डॉ. फारुक जी. पटेल ने कहा, 'कोल इंडिया जैसे प्रतिष्ठित और बड़े संगठन के साथ इस स्तर की परियोजना पर काम करना, केपीआई ग्रीन एनर्जी की यूटिलिटी-स्केल सौर परियोजनाओं में हमारी क्षमता पर बाजार के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है.

हम आने वाले महीनों में परियोजना की शेष क्षमता को भी सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे भारत के अग्रणी सोलर ईपीसी खिलाड़ियों में हमारी स्थिति और मजबूत होगी.

> कंपनी ने कहा है कि इस परियोजना के चालू होना से केपी ग्रुप के वर्ष 2030 तक 10,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो विकसित करने के घोषित लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

7 महीने में पैसा डबल, सालभर में 3 गुना रिटर्न!

नई दिल्ली, 20 जुलाई शेयर बाजार में कुछ कंपनियों के स्टॉक कम समय में ही निवेशकों की किस्मत बदल देते हैं. ऐसा ही प्रदर्शन आदित्य इन्फोटेक के शेयर ने किया है. सीसीटीवी कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सॉल्यूशन क्षेत्र में काम करने वाली इस कंपनी के शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है. महज 7 महीने में इस मल्टीबैगर स्टॉक ने निवेशकों का पैसा लगभग दोगुना कर दिया, जबकि एक साल के दौरान इसमें करीब तीन गुना तक उछाल देखने को मिला है.आदित्य इन्फोटेक का शेयर साल 2026 में अब तक 137 फीसदी तक बढ़ चुका है. कंपनी का स्टॉक साल 2025 में शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुआ था और लिस्टिंग के बाद से ही इसमें लगातार तेजी बनी हुई है.

भारत को मिली पहली डेंगू वैक्सीन 'क्यूडेंगा' की मंजूरी

नई दिल्ली। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल (डीसीजीआई) ने टाकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स इंडिया की डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को 4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। यह भारत में मंजूरी पाने वाली पहली डेंगू वैक्सीन है, जिसे पहले डेंगू संक्रमण हुआ हो या नहीं, दोनों ही परिस्थितियों में लगाया जा सकता है और इसके लिए टीकाकरण से पहले किसी जांच की आवश्यकता नहीं होती।

कंपनी के अनुसार, क्यूडेंगा डेंगू वायरस के सभी चारों सीरोटाइप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विकसित की गई है। यह मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब पिछले दो दशकों में भारत में डेंगू के मामलों में 11 गुना वृद्धि दर्ज की गई है और वर्ष 2025 में देश में 1.13 लाख से अधिक मामले सामने आए थे।

डब्ल्यूएचओ कर चुका है सिफारिश -कंपनी ने बताया कि क्यूडेंगा को भारत सहित 43 देशों में मंजूरी मिल चुकी है तथा अब तक इसकी 3.2 करोड़ से अधिक डोज सार्वजनिक और निजी टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से वितरित की जा चुकी हैं। 28 हजार से अधिक प्रतिभागियों पर किए गए वैश्विक क्लीनिकल परीक्षणों में वैक्सीन ने डेंगू संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा दिखाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) भी डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में इसके उपयोग की सिफारिश कर चुका है। टाकेडा ने कहा कि डीसीजीआई की मंजूरी के बाद वह भारतीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों के साथ मिलकर देश में वैक्सीन की उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेगी।

आधार की सुरक्षा बढ़ाएं, ऐप से ऐसे करें बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक

नई दिल्ली, 20 जुलाई आधार कार्ड आज हर नागरिक की पहचान से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है. बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, मोबाइल कनेक्शन और कई अन्य सेवाओं के लिए आधार का इस्तेमाल किया जाता है.

आधार में मौजूद व्यक्तिगत जानकारी और बायोमेट्रिक डेटा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक की सुविधा उपलब्ध कराई है.इस फीचर की मदद से आधार धारक अपने फिंगरप्रिंट, आइरिस और फेस ऑथेंटिकेशन को जरूरत के अनुसार लॉक कर सकते हैं. बायोमेट्रिक लॉक होने के बाद कोई भी व्यक्ति या संस्था आपके आधार नंबर के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कर पाएगी. अगर कोई लॉक अवधि के दौरान ऑथेंटिकेशन की कोशिश करता है, तो वह प्रक्रिया सफल नहीं होगी.

नीट 2026 में एलन का दबदबा कायम

कोलकाता केंद्र के 3 छात्रों ने टॉप-1000 में बनाई जगह, 5 छात्र टॉप-1600 रैंक में शामिल

कोलकाता, 20 जुलाई. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा घोषित नीट-यूजी 2026 के परिणामों में एलन करियर इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।

राष्ट्रीय स्तर पर जहां एलन के विद्यार्थियों ने शीर्ष रैंक हासिल कर संस्थान का नाम रोशन किया, वहीं एलन कोलकाता केंद्र के छात्रों ने भी शानदार सफलता दर्ज कराई। कोलकाता केंद्र के तीन छात्रों ने ऑल इंडिया रैंक (एआईआर) की टॉप-1000 सूची में स्थान बनाया, जबकि पांच छात्र टॉप-1600 रैंक में शामिल हुए। इस उपलब्धि ने एक बार फिर एलन की शैक्षणिक गुणवत्ता और विद्यार्थियों की मेहनत को साबित किया है. एलन कोलकाता सेंटर हेड देबाशीष सान्याल ने परिणामों पर खुशी जताते हुए कहा कि एलन अपनी उत्कृष्ट शैक्षणिक परंपरा और लगातार बेहतर परिणामों के लिए जाना जाता है। इस वर्ष भी संस्थान ने उसी भरोसे को कायम रखा है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों द्वारा संस्थान पर जताए गए विश्वास का ही परिणाम है कि एलन कोलकाता के छात्र लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहेगा।कोलकाता केंद्र के परिणामों में अरित्रा कृष्ण चक्रवर्ती ने 680 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक 284 हासिल की।

समाचार विशेष

हाईकमान का अंदरूनी कलह पर सख्त रुख

प्रदेश अध्यक्ष बदलना गुड्डे-गुड़ियों का खेल नहीं...

नई दिल्ली. अगले विधानसभा चुनाव के लिए सिरदर्द बने पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी घमासान का नए सिरे से समाधान निकालने के लिए पार्टी ने शीर्ष स्तर पर बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया है.

इसके साथ ही कांग्रेस नेतृत्व ने साफ संकेत दे दिया है कि बगावत का झंडा उठाकर पार्टी हित की कीमत पर निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधने के प्रयासों को सहन नहीं किया जाएगा.

हाईकमान ने यह इशारा भी कर दिया है कि गुटबाजी और सार्वजनिक बयानबाजी के जरिये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने का दबाव बनाने का पैंतरा भी स्वीकार्य नहीं है. पंजाब कांग्रेस के प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सूबे में पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी से संबंधित अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद कहा कि प्रदेश का पार्टी प्रधान बदलना कोई गुड्डे-गुड़ियों का खेल नहीं है.

कांग्रेस हाईकमान के इन संदेशों से साफ है कि पंजाब में अंदरूनी कलह का हल आपसी बातचीत और सद्भाव से ही निकाला जाएगा तथा किसी एक गुट के दबाव में पार्टी हित की कुर्बानी नहीं दी जाएगी. बघेल द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के बाद पार्टी सूत्रों की ओर से संकेत साफ हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सीधे तौर पर शायद ही गुटबाजी के संदर्भ में पंजाब के नेताओं से बातचीत करेंगे. इसके बजाय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को हटाने के लिए विद्रोह का झंडा उठाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से लेकर सुखजिंदर सिंध रंधावा जैसे तमाम नेताओं से बातचीत करेंगे.

अंदरूनी विवाद का हल निकालने का जिम्मा शीर्ष नेतृत्व ने वेणुगोपाल को सौंपा है. यह बुधवार सुबह स्पष्ट भी हो गया जब भूपेश बघेल ने उनसे मुलाकात कर पंजाब संकट पर अपनी रिपोर्ट उनको सौंपी.

> **चन्नी और रंधावा के व्यवहार से हाईकमान क्षुब्ध**
>
> इस संदर्भ में वेणुगोपाल अगले एक-दो दिनों में पंजाब से कांग्रेस के सांसदों से भी मशविरा करेंगे तथा हाईकमान के दृष्टिकोण से उन्हें रूबरू कराएंगे. पार्टी सूत्रों के दावों से स्पष्ट है कि हाईकमान चन्नी और रंधावा जैसे अपने वरिष्ठ नेताओं के व्यवहार से क्षुब्ध है. इसलिए पंजाब के नाराज नेताओं से बातचीत में वेणुगोपाल यह स्पष्ट संदेश देने से गुरेज नहीं करेंगे कि दबाव की राजनीति का दांव चलकर पंजाब कांग्रेस के व्यापक हित में लिए गए फैसलों को बदलवाया नहीं जा सकता.

वार्ड समितियों में भाजपा का दबदबा

12 में से 10 पर कब्जा, छोटे चुनाव में आप को बड़ा झटका

नई दिल्ली. एमसीडी की 12 वार्ड समितियों के चुनाव में भाजपा ने अपनी राजनीतिक बढ़त को और मजबूत करते हुए 10 समितियों के अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया.

पिछले साल भाजपा आठ और आम आदमी पार्टी (आप) चार वार्ड समितियों में अध्यक्ष पद जीतने में सफल रही थी, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई. भाजपा ने आप के कब्जे वाली शहरी-सदर पहाड़गंज (सिटी एसपी) और पश्चिमी वार्ड समिति भी अपने नाम कर ली.

वहीं आप केवल रोहिणी और करोल बाग वार्ड समिति तक सिमट गई. हालांकि भाजपा की इस बड़ी जीत के बीच सबसे बड़ा झटका उसे महापौर प्रवेश वाही के प्रभाव वाले रोहिणी जोन में लगा. यहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर भाजपा उम्मीदवारों को एक-एक वोट से हार का सामना करना पड़ा.

> **मतदान के पहले आप पार्षद भगवा हो गए**
>
> सबसे नाटकीय घटनाक्रम शहरी-सदर पहाड़गंज (सिटी एसपी) वार्ड समिति में देखने को मिला. मतदान शुरू होने से करीब ढाई घंटे पहले आप के पार्षद विकास टांक भाजपा में शामिल हो गए. इस घटनाक्रम ने समिति का पूरा गणित बदल दिया. भाजपा उम्मीदवार उषा शर्मा ने अध्यक्ष पद पर 7-5 से जीत दर्ज कर यह समिति आप से छीन ली. दिलचस्प यह भी रहा कि आप के एक अन्य पार्षद और अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्षद ने भी भाजपा के पक्ष में मतदान किया.

छोटी पार्टियों पर भाजपा की नजर

नई दिल्ली. ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बड़ी पार्टियों को तोड़ कर संसद के मानसून सत्र में दो तिहाई बहुमत जुटाने का प्रयास कर रही है.

कई छोटी पार्टियों पर नजर है और उनके लिए परदे के पीछे से बात हो रही है. जानकार सूत्रों का कहना है कि झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर जम्मू कश्मीर की नेशनल कान्फ्रेंस और दिल्ली व पंजाब की आम आदमी पार्टी के सांसदों से भी बात हो रही है. कहा जा रहा है कि अगर इन पार्टियों के नेता संसद के मानसून सत्र में संविधान संशोधन के लिए लाए जाने वाले विधेयकों पर सरकार का समर्थन नहीं करते हैं तो इनकी पार्टियां भी टूटेंगी. गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसद टूट चुके हैं.

गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीन, आम आदमी पार्टी के तीन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो लोकसभा सांसद हैं. इन आठ सांसदों पर भाजपा की नजर है. अगर इनके नेता तैयार हो जाते हैं तो कहा जाएगा कि वे वोटिंग के समय सदन से गैरहाजिर हो जाएं. इनमें से जेएमएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों के टूटने की संभावना कम है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को पता है कि वे श्रीनगर और अनंतनाग की सीट से भाजपा की टिकट पर नहीं जीत सकते हैं.

विशेष क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल?

360 के मैजिक नंबर से सिर्फ 6 कदम दूर एनडीए!

नई दिल्ली. संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले डीलिमिटेशन (परिसीमन) बिल को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. पिछले संसद सत्र में मोदी सरकार इस विधेयक को दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण पारित नहीं करा सकी थी. उस समय सरकार को जरूरी 360 वोटों के मुकाबले 54 वोट कम पड़ गए थे.

अब बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के बीच माना जा रहा है कि सरकार एक बार फिर इस बिल को सदन में ला सकती है. लोकसभा में फिलहाल 540 सदस्य हैं और किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए 360 सांसदों का समर्थन जरूरी है. एनडीए के पास 298 सांसद हैं. यदि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 20 बागी और उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद सरकार के साथ आते हैं तो यह संख्या 324 तक पहुंच जाती है. इसके बावजूद सरकार बहुमत से 36 वोट दूर रहती है.

डीएमके और एनसीपी (एस) पर टिकी निगाहें सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि अगर डीएमके के 22 सांसद और शरद पवार की एनसीपी (शरद पवार) के 8 सांसद सरकार का समर्थन करते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 354 तक पहुंच सकता है. हालांकि इसके बाद भी सरकार दो-तिहाई बहुमत से 6 वोट पीछे रहेगी. ऐसे में छोटे दलों और निर्दलीय सांसदों की भूमिका बेहद अहम हो सकती है.

सुप्रिया ने किया 50 प्रतिशत सीट बढ़ाने वाले फॉर्मूले का जिक्र- वहीं एनसीपी (शरद पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने खुलासा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पहले सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव रखा था. उन्होंने कहा कि अगर पूरे देश में समान रूप से 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव आता है तो इस पर विचार किया जा सकता है.

> **क्या इंडिया गठबंधन में बढ़ेगी मुश्किल?**
>
> सुप्रिया सुले के इस बयान के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन में नई चर्चा शुरू हो गई है. अब राजनीतिक नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या शरद पवार और डीएमके सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे या फिर विपक्ष की एकजुटता बरकरार रहेगी. हालांकि सुप्रिया सुले ने एनडीए में शामिल होने की अटकलों को पूरी तरह खारिज किया और कहा कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ही बड़े राजनीतिक फैसले लेगी. अब सबकी नजर सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में यदि डीलिमिटेशन बिल पेश होता है तो यह मौजूदा राजनीतिक माहौल की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है.